

5-

**समाहरणालय, पटना।**  
(शस्त्र शाखा)

5-24/13  
फोन नं० 0612-2219545 (का०)  
फैक्स नं०-0612-2218900  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

-: आदेश :-

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-9-558/2008 में आवेदक मो० महताब आलम, पिता-मो० वशी, सा०-अशोक राजपथ, बिहार साव लेन, थाना-पीरबहोर, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-04.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे मोबाईल टावर के निर्माण एवं अधिष्ठापन का काम करते हैं। उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-179/गो०, दिनांक-30.01.2011 द्वारा आवेदक का अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अधिनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में मात्र अग्रसारित किया गया है, अनुशंसा अंकित नहीं है। पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पीरबहोर के अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अनुशंसित एवं अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, पीरबहोर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक मोबाईल टावर के निर्माण एवं अधिष्ठापन का काम करते हैं। पूर्व में इनके पिता के नाम से एक एन०पी०बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं०-170107-1076 है। लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गई है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

आवेदक के आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय लंबित रहने के कारण शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु पटना उच्च न्यायालय, पटना में अपील याचिका दायर किया गया, जिसमें सी०डब्लू०जे०सी० सं०-22212/2012 महताब आलम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में न्यायालय द्वारा दिनांक-05.12.2012 को आदेश पारित किया गया, जिसमें आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर तीन माह के अंदर अंतिम आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है। नियत समय सीमा में अंतिम आदेश पारित नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एम०जे०सी० सं०-...../2013 भी दायर किया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 की कंडिका-II में एन०पी०बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :-

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका-II की उप कंडिका-b तथा e निम्नवत है :-

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

7

5-24/12

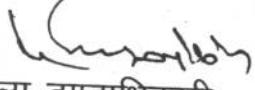
e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक मो० महताब आलम को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एन०पी०बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। साथ ही उल्लेखनीय है कि आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक मो० महताब आलम, पिता-मो० वशी, सा०-अशोक राजपथ, बिहार साव लेन, थाना-पीरबहोर, जिला-पटना के आवेदित एक एन०पी०बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

  
जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।